नयी आर्थिक नीति

रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स नं० १५

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९ सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई अंक ४४

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ३१ दिसम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

हमारी बुनियादी आर्थिक दृष्टि

अगर आप मुझे अिजाजत दें तो मैं कर्वे-रिपोर्टके बारेमें कुछ कहूंगा; क्योंकि मुझे लगता है कि अिस प्रश्न पर बड़ी गलत-फहमी, गलत डर और भ्रम लोगोंमें फैला हुआ है। किसी खास समय किसी खास बात पर जोर देनेके बारेमें मतभेद जरूर हो सकता है।

अब हमारी बुनियादी दृष्टियां क्या हैं? अेक दृष्टि यह है कि हम कुदरती तौर पर अुत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, देशकी सम्पत्तिमें वृद्धि करना चाहते हैं, देशमें अधिकाधिक अुद्योग-धन्धे बढ़ाना चाहते हैं। मैं नहीं मानता कि देशमें बड़े पैमाने पर अुद्योग-धन्धे खोले बिना और अुत्पादनकी नअीसे नअी पद्धतियां अपनाये बिना हम भारी तरक्की कर सकेंगे। बड़े पैमानेसे मेरा मतलब सिर्फ बड़े अुद्योगोंसे नहीं, बल्कि व्यापक पैमाने पर अुद्योग-धन्धे खोलनेसे भी है। अगर हम लोग लोहे और फौलादके कारखानोंका विकास करना चाहते हैं, तो हमारे देशमें लोहे और फौलादके नयेसे नये यंत्रोंवाले कारखाने होने चाहिये। अगर हम रेलके अेंजिनका कारखाना रखना चाहते हैं तो वह नयेसे नये ढंगका होना चाहिये। अगर हमारे पास, फर्ज कीजिये, सीमेन्टका कारखाना हो, खादका कारखाना हो, रक्षाके लिअे हथियार तैयार करनेवाले कारखाने हों या सबसे अधिक बुनियादी और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यंत्र बनानेवाले कारखाने हों, तो वे नयेसे नये ढंग और नअीसे नअी पद्धतिके होने चाहिये। हम पुरानी पद्धतियोंसे काम चलाकर न तो दूसरे देशोंकी होड़में खड़े रह सकते हैं और न ज्यादा माल अुत्पन्न कर सकते हैं। यह अेक दृष्टि हुअी।

दूसरी और अुतनी ही महत्त्वकी दृष्टि है लोगोंको कामधन्धा देनेके बारेमें। देशमें बेकारीका होना, खास करके बड़े पैमाने पर बेकारीका होना, हमें पुसा नहीं सकता। लोगोंको काम देना केवल हमारा फर्ज ही नहीं, सामाजिक आवश्यकता भी है। अगर हम यह व्यवस्था नहीं करते तो दोनों तरफसे मुसीबत खड़ी होती है।

अब हमें अिन दोनों दृष्टियोंके बीच सन्तुलन कायम करना है, और सन्तुलन कायम करनेमें कअी बातोंका विचार करना होता है। दूसरी कअी सामाजिक बातोंका विचार करना होता है। बेशक, अुद्योगीकरणके पुराने पूंजीवादी रूपके खिलाफ अेक बड़ी आपत्ति यह है कि वह जिस सामाजिक दुःख-दर्दको पैदा करता है, अुसकी बिलकुल परवाह नहीं करता, हालांकि आखिरमें वह देशका अुत्पादन जरूर बढ़ाता है। सच पूछा जाय तो मार्क्सकी पुस्तक 'केपिटल' शुरूसे आखिर तक अिंग्लैण्डमें हुअे अुद्योगीकरणके विकासकी और अुसके कारण पैदा हुअी भयंकर मुसीबतोंकी ही चर्चा करती है। दरअसल साम्यवादी दृष्टिकोणका सारा आधार अिंग्लैण्डमें १९ वीं सदीमें जो कुछ हुआ अुसी पर है। वह अब पुराना पड़ गया है। आज कोअी अुसे दुहरा नहीं सकता और न कोअी अुसे किसी देशमें दुहराना चाहता है। हम भी अपने देशमें अुसे दुहरा नहीं सकते, क्योंकि लोग अुसे बरदाश्त नहीं करते। और न हम अुसे दुहराना ही चाहते हैं।

अिसलिअे अुत्पादनकी नअीसे नअी पद्धतियां अपनानेके सिद्धान्त पर कायम रहते हुअे लोगोंको कामधन्धा देनेकी बात पर अुसके असरका विचार करके हमें अुसकी गति पर हमेशा संयम रखना होगा। अगर कोअी चीज बेकारी पैदा करती हो तो हमें विचार करना होगा कि अुस सम्बन्धमें क्या किया जाय, क्योंकि बेकारीका पूंजीवादी दृष्टिसे विचार करने पर भी यह देखना हमारा फर्ज हो जाता है कि अगर हम लोगोंको कामधन्धा न दे सकें तो हमें अुन्हें 'डोल' देना चाहिये। अिंग्लैण्डको और अुसके जैसे दूसरे देशोंको यही करना पड़ता है। बहुतायतसे मालका अुत्पादन करके वे अपने बेकार नागरिकोंको 'डोल' देते हैं। हमें अपने अेक करोड़ लोगोंको 'डोल' देना पुसा नहीं सकता। 'डोल' देना बुरी बात भी है। 'डोल' देनेके बदले काम देना कहीं बेहतर है, भले वह काम आर्थिक दृष्टिसे नुकसान पहुंचाता हो। हम घटिया पद्धतियोंसे काम करके अिस दुनियाके दूसरे देशोंकी होड़में खड़े नहीं रह सकते; और हम अपने बड़े अुद्योगों और मध्यम अुद्योगोंमें अूंची पद्धतियां अपनाकर दूसरे किसी अुद्योगमें पुरानी पद्धतिसे काम नहीं कर सकते। लेकिन अैसी नीति पर चलना और भी बुरा है, जो अेकदम न सही परन्तु धीरे-धीरे भी यथाशक्ति बेकारीकी समस्या हल करनेमें हमारी मदद नहीं करती। पैदा होनेवाली सामाजिक मुसीबतोंके खयालसे और दूसरी कअी दृष्टियोंसे भी, व्यापक पैमाने पर लोगोंको कामधन्धा देना कहीं ज्यादा अच्छा है। कामधन्धेके फैलावसे पैदा होनेवाली खरीद-शक्ति देशकी आर्थिक व्यवस्थाको ज्यादा तेजीसे आगे बढ़ाती है। अिन सिद्धान्तोंको स्वीकार करके यह सोचना होगा कि अुनमें सन्तुलन कैसे कायम किया जाय? सन्तुलनका ध्यान हमें हमेशा रखना होगा।

जहां तक अम्बर चरखेका सम्बन्ध है, अगर मैं कह सकूं तो अुसकी कीमत अंतिम रूपसे नहीं आंकी गअी है। अैसा करनेके दो रास्ते हैं। अेक रास्ता यह है कि निष्णात लोग अुसे कुछ महीने चलायें और अपनी राय दें। दूसरा और शायद बेहतर रास्ता यह है कि सैकड़ों-हजारों व्यक्ति, साधारण लोग, अुस पर काम करें और हम अिसका पता लगायें कि अुन्होंने अुस पर कैसे काम किया है; क्योंकि वही सच्ची कसौटी है। अब यही किया जा रहा है। अभी तक जो नतीजे आये हैं, वे कुल मिलाकर सन्तोषप्रद हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी हम बिचली मंजिल पर हैं। लेकिन वह हमें आशा, काफी आशा, बंधाती है। अम्बर चरखा कुछ हजार लोगोंमें बांटा जा रहा है; अुनका अनुभव और अुनकी रिपोर्ट बहुत मददगार साबित होगी। अुसकी परीक्षा करनेवाले

www.vinoba.in

कुछ विशेषज्ञ लोगोंकी टेकनिकल रिपोर्टको छोड़ दें, तो आज भी वह आशाप्रद मालूम होता है और बेशक, अगर मैं अैसा कह सकूं, हमारी आशासे भी कुछ बढ़कर मालूम होता है।

लेकिन अंबर चरखा अिस विषयमें कोअी अंतिम चीज नहीं है। आजके अम्बर चरखेमें भी अुपयोग करनेसे सुधार हो सकता है। जाहिर है कि अभ्यास और अुपयोगसे अुसमें सुधार हो सकते हैं। और वह ज्यादा और ज्यादा अुपयोगी औजार बनाया जा सकता है। अिसके लिअे कोअी कारण नहीं है कि अम्बर चरखा या दूसरी कोअी छोटी घरेलू मशीन समय आने पर बिजलीकी शक्तिका अुपयोग न करे, ताकि बेकारीकी समस्याका हमेशा खयाल रखते हुअे धीरे धीरे वह छोटी मशीन भी टेकनिकल दृष्टिसे कार्य-क्षम बन जाय। अिसकी पूरी तरह कल्पना की जा सकती है, बेशक यह संभव हो सकता है, कि अम्बर चरखेके मौजूदा डिज़ाअिनसे नहीं तो अुसके कुछ सुधरे हुअे डिजाअिनसे हम बड़े पैमानेकी अुत्पादनकी पद्धतिको प्राप्त कर सकते हैं। छोटे पैमानेकी अुत्पादन पद्धतिका अेक लाभ यह है कि हमें मालको अेक जगहसे दूसरी जगह नहीं भेजना पड़ता और अिस तरह मालकी लागत कीमत कम हो जाती है। अिसमें कोअी शक नहीं कि वह बड़ी मशीनके बनिस्बत आर्थिक दृष्टिसे कम कार्यक्षम होगी। हमें दोनोंके बीच सन्तुलन कायम करना होगा। यह सचमुच अेक बड़ा सवाल हो जाता है — हवामें दलीलें करनेका नहीं बल्कि अिन सब बातोंका विचार करनेका और लोगोंको कामधन्धा देनेकी बातको देखने और सबसे पहले तरजीह देनेका।

खादी-ग्रामोद्योग बोर्डने अगले पांच वर्षोंके लिअे अेक कार्य-क्रम बनाया है। कामकी कुछ कल्पना होनेके लिअे, चर्चा करनेके लिअे, हमारे सामने योजनाका होना अच्छी बात है। लेकिन सच पूछा जाय तो अुसका आधार कअी अनिश्चित बातों पर है। समय बीतने पर, आजसे छः महीने बाद, हम अम्बर चरखेके बारेमें कुछ कहनेके लिअे ज्यादा अच्छी स्थितिमें रहेंगे। अगले वर्ष, व्यापक पैमाने पर अुसकी अुत्पादक शक्तिको जाननेके बाद हम अुसके बारेमें बात करनेके लिअे और भी ज्यादा अच्छी स्थितिमें होंगे। आज हम जो कार्यक्रम बनाते हैं वह केवल अस्थायी कार्यक्रम होगा, जिसकी कीमत दरअसल अेक वर्ष या दो वर्ष बाद आंकी जानी चाहिये और अुसके आधार पर अुसमें फेरबदल करना चाहिये। परिणामके लिअे हमें अगले दो वर्षों पर दृष्टि रखनी चाहिये और प्रति वर्षके परिणाम परसे अुसकी कीमतकी जांच करनी चाहिये।

अिसका अेक तीसरा पहलू भी है। अुसका संबंध अिस देशमें होनेवाली कपड़ेकी खपतका अन्दाज लगानेसे है। कपड़ेकी खपत अिस देशमें काफी तेजीसे बढ़ रही है, अुसकी गति धीमी होते हुअे भी कुल मिलाकर वह बहुत बड़ी हो जाती है। अगर हम अन्दाज लगायें — भले वह अन्दाज कुछ भी हो — और अुसके अनुसार हिसाब करें तो वह बहुत अच्छी बात है। अगर कपड़ेकी मांग अुससे कहीं ज्यादा हो तो अुत्पादन पिछड़ जाता है। अैसी हालतमें भाव बढ़ जाते हैं और कठिनाअियां व मुद्राप्रसार जन्म लेता है। हम यह सब टालना चाहते हैं। हम अिस बारेमें कोअी जोखिम नहीं अुठाना चाहते, मांगको दोनों तरफकी पूर्तिसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और अुसकी वजहसे दूसरी अैसी हालतें पैदा नहीं होने देना चाहते, जिनका न केवल हमारी कपड़ेकी स्थिति पर बल्कि हमारी संपूर्ण अर्थ-रचना पर बुरा असर पड़े। अिसलिअे हमें यह विचार करना होगा कि अम्बर चरखा कितनी तेजीसे सूतका अुत्पादन कर सकता है। अंबर चरखेके संबंधमें खास कठिनाअी अुसके काम करनेकी नहीं है। वह अच्छा काम दे सकता है। लेकिन खास कठिनाअी अुसे हजारों गांवोंमें फैलानेकी है। खास कठिनाअी अुसकी व्यवस्था करनेकी है। किसी बड़े लोहे और फौलादके कारखानेकी व्यवस्था करना तुलनामें आसान है, लेकिन अैसी किसी चीजकी व्यवस्था करना कठिन है, जो ५० हजारसे ज्यादा गांवोंमें फैली हुअी हो। अगर अुस चरखेमें कोअी थोड़ा बहुत बिगाड़ हो जाय तो अुसे सुधारनेकी दूसरी समस्या है। लोगों तक कच्चा माल पहुंचाना और सूत अिकट्ठा करना अपने-आपमें अेक जबरदस्त काम है। अगर यह चरखा संतोषप्रद ढंगसे काम न करे तो अुत्पादनमें कमी हो सकती है। अिसलिअे कम अुत्पादनके बजाय अधिक अुत्पादनकी गलती करना बेहतर होगा। अतः हमें अुस दृष्टिसे यह विचार करना होगा कि मिलोंमें या दूसरी जगह कितने तकुओंकी जरूरत होगी। अगर हिसाब करके मालूम हो जाय कि मिलोंमें काफी तकुअे हैं तो कोअी कठिनाअी नहीं रह जाती। लेकिन अगर हमारे पास काफी तकुअे न हों, तो हमें यह विचार करना होगा कि किस हद तक अुनकी वृद्धिको प्रोत्साहन दिया जाय। अिस तरह ये सारी बातें केवल सैद्धान्तिक दलीलों या सिद्धान्तोंकी बातें नहीं, बल्कि तथ्योंका सावधानीपूर्वक विचार करनेके प्रश्न बन जाती हैं।

हमें यह बताया गया था कि अिस समय मिलोंमें अुत्पादनकी खासी अच्छी क्षमता है; जरूरत पड़ी तो तीसरी पाली शुरू की जा सकती है, और भी ज्यादा जरूरत मालूम हुअी तो आज जो तकुअे मिलोंमें निकम्मे पड़े हुअे हैं अुन्हें काममें लिया जा सकता है। अिस बात पर हमें विचार करना चाहिये। मेरा मुद्दा यह है कि यह प्रश्न अूंचे सिद्धान्तका नहीं है, बल्कि हमारी आजकी कपड़ा-स्थिति पर सावधानीसे विस्तृत विचार करनेका है, ताकि हम अम्बर चरखेको यथासंभव ज्यादासे ज्यादा तेजीसे फैला सकें, अुसके नतीजे देखें, तथा अुसे फैलाते जायं और साथ ही अिस बातका भी ध्यान रखें कि देशमें बढ़नेवाली मांग और खपतके कारण कपड़ेकी तंगी पैदा न हो। मैं केवल अूंचे सिद्धान्तोंके बारेमें दलील नहीं चाहता, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं हमारी बुनियादी दृष्टिमें कोअी भेद नहीं है। अिस या अुस बात पर जोर देनेके बारेमें मतभेद हो सकता है। हमें अिन सिद्धान्तोंको अपने सामने रखकर और काममें कोअी बड़ा जोखिम न अुठाकर आजमाअिश और गलतीके तरीकेसे आगे बढ़ना है।

अम्बर चरखेको दोनों तरहसे विकास करनेका हर मौका दिया जाना चाहिये। अेक, मौजूदा अम्बर चरखेको व्यापकसे व्यापक पैमाने पर आजमाना चाहिये। दूसरे, अुसका विकास करनेके लिअे अुसमें हर तरहके आवश्यक टेकनिकल सुधार करने चाहिये। अितना कहनेके बाद, दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमें मिलोंमें किस हद तक तकुअे बढ़ानेको प्रोत्साहन देना चाहिये? यह हिसाब करने और अन्दाज कूतनेकी बात है। जैसे जैसे अम्बर चरखेके कामके नतीजे हमें मालूम होते जायंगे, वैसे वैसे हमारा हिसाब ज्यादा और ज्यादा निश्चित होता जायगा। अिस पर हवामें चर्चा करनेसे कोअी लाभ नहीं होगा। सिद्धान्तोंके साथ मैं सहमत हूं, और अुनमें से अेक सिद्धान्त यह है कि हमें अम्बर चरखेको अधिकसे अधिक आगे बढ़ाना है। अिसके खिलाफ यह दलील पेश की जाती है: अम्बर चरखेको आगे बढ़ानेसे क्या लाभ होगा, अगर आप अम्बर चरखे द्वारा पैदा किया हुआ सारा सूत काममें नहीं ले सकते? यह बहुत ठोस दलील है। बेशक, पहले हमें अम्बर चरखे द्वारा पैदा किये जानेवाले अच्छे सूतको काममें लेनेकी गारंटी देनी चाहिये और बादमें अम्बर चरखेको फैलाना चाहिये।

अिसके सिवा, हमारी आजकलकी अर्थ-रचना सौभाग्यसे विकास करनेवाली अर्थ-रचना है। लेकिन हमारा झुकाव स्थिर अर्थ-रचनाका विचार करनेकी ओर होता है। विकास करनेवाली अर्थ-रचनाका

www.vinoba.in

अर्थ है अधिक संपत्ति, अधिक खरीद-शक्ति और मालका अधिक अुत्पादन। अगर हम स्थिर अर्थ-रचनाकी भाषामें विचार करते हैं, तो हम अपनी अर्थ-रचनाके विकास पर रोक लगा देते हैं। ये सारी कठिनाअियां खड़ी होती हैं। केवल कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित मार्गोंकी चर्चा करना बेकार है। ये मार्ग अपने-आपमें अच्छे हैं, लेकिन हमें तो नीचे अुतर कर तथ्यों और आंकड़ोंका विचार करना चाहिये।

अेक और बात भी है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिये। हमारे विकासके बावजूद हमारी बड़ी बड़ी विकास-योजनाओंके कारण हमारी आय पर बहुत जोर पड़ रहा है। हमारे कूते हुअे साधनों और हम जो कुछ खर्च करनेका अिरादा रखते हैं, अिन दोनोंके बीच बड़ी खाअी है। आम तौर पर हम किसी अधिक बड़े प्रयत्नसे और संभवतः बड़ी हद तक किसी बाहरी मददसे अिस खाअीको पूरना चाहेंगे। बाहरी मदद मिल सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बाहरी मदद पर भरोसा रखनेके बारेमें हम बहुत निश्चित रह सकते हैं। और चूंकि बाहरी दुनियामें आज अनेक घटनायें घट रही हैं, अिसलिअे संभव है बाहरी मदद मांगना आजकी स्थितिमें हमारे लिअे वांछनीय न हो।*

(अंग्रेजीसे) **जवाहरलाल नेहरू**

टिप्पणियां

संकुचित वृत्तिसे सावधान रहें

ता० १५–११–'५५ को मद्रासके अेक भाषणमें बोलते हुअे डॉ० राजेन्द्रप्रसादने अेक बातके बारेमें, जो देशके दूसरे भी कअी लोगोंको दुःख पहुंचाती है, नीचेके शब्दोंमें अपना दुःख प्रकट किया:

"यह देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि गांधीजीके अवसानके बाद अितनी जल्दी हम अुन बहुतेरी चीजोंको कैसे भूल गये, जो गांधीजीके जीवनकालमें हमें बहुत स्पष्ट, खुली और स्वयंसिद्ध जैसी दिखाअी देती थीं। यह सचमुच बड़े आश्चर्यका विषय है कि बहुतसे मामलोंमें हमें अुन बातोंके बारेमें न केवल सबूतकी जरूरत मालूम होती है, बल्कि वे गलत भी मालूम होती हैं।

"वह बुनियादी बात क्या थी, जो गांधीजीने कही थी? अलबत्ता, अुन्होंने हमारे लोगोंकी आर्थिक दशा सुधारनेके महत्त्व पर, अुनकी भूख और बीमारीको मिटाने पर जोर दिया था; वे अिन सब बातोंसे अनजान नहीं थे, न अुन्होंने अिनकी कभी अुपेक्षा की। सच पूछा जाय तो अिन बुराअियोंको दूर करनेके लिअे अुन्होंने भरसक प्रयत्न किया। लेकिन साथ ही अिस सारी चीजको अुन्होंने आत्मा और सदाचारकी पक्की नींव पर खड़ा किया था। आज हम अिस नींवको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर अुस नींव पर आधार रखें तो भविष्यमें हम अपने काम सही ढंगसे और दृढ़तापूर्वक चला सकेंगे।"

अैसे ही दुखी मनसे कांग्रेसके अध्यक्षने पिछले अपने आसामके दौरेमें कहा था कि स्वतंत्र भारतमें पहला और सबसे बड़ा संकट यह दिखाअी देता है कि हमारी आत्मत्याग और बलिदानकी भावना नष्ट हो गअी है। यह हमारे राष्ट्रकी अेक बड़ी पूंजी थी, जिसके बल पर आजादीके लिअे हमने प्रयत्न किया और अुसे हासिल किया। अिस भावनाके नष्ट हो जानेका ताजेसे ताजा सबूत आज हम राज्य-पुनर्रचनाके बारेमें तथा अुस प्रश्नको देखनेकी लोगोंकी वृत्ति और मानसमें देख रहे हैं। अिस दुःखद तसवीरको देखकर कुछ लोग अैसा कहने लगे हैं कि हमें अिस सवालको कुछ समयके लिअे मुलतवी कर देना चाहिये। स्पष्ट ही यह निराशाकी सलाह है — अैसा अिनकार है जिससे कोअी मदद नहीं हो सकती। देरी अिस सवालको हमारे लिअे हल नहीं कर देगी, क्योंकि जब कभी हम फिरसे अिस सवालको हाथमें लेंगे हमारे सामने यही कठिनाअी आयेगी, अगर हमारी वृत्ति और मानस वैसा ही रहेगा जैसा कि आज हम प्रगट कर रहे हैं। अिसलिअे हमें अपनी वृत्ति और मानसको बदलना चाहिये, सामूहिक बुद्धिमत्ता तथा अधिकसे अधिक सयानपनसे अिस सवालका सामना करना चाहिये और अैसे निर्णय पर पहुंचना चाहिये, जो माने हुअे ध्येयकी ओर हमारी प्रजाको आगे बढ़ानेमें सहायक सिद्ध हो। हमें संकुचित या अेक भाषाके प्रान्तीयवादसे अूपर अुठना चाहिये, जो आज हम पर बुरी तरह हावी हो गया मालूम होता है।

२०–१२–'५५ **म० प्र०**

(अंग्रेजीसे)

गलत समझ

मध्यभारतसे अेक भाअी लिखते हैं:

"मध्यभारत भूदान-यज्ञ-समितिका अेक पंद्रह दिवसका शिविर रतलामके पासके अेक गांवमें हुआ था। अुसमें अनेक अुच्च कोटिके विद्वानोंके भाषण और शरीर-श्रमके कार्य हुअे। परंतु शिविरमें कुछ लोगोंके और कुछ स्त्री-पुरुषोंके अेक ही थाली-कटोरीमें भोजन करने पर जब अुनसे कहा गया कि अिस प्रकारका सहभोज स्वास्थ्यके नियमोंके विपरीत है, तो बहुतसे प्रमुख कार्यकर्ताओं तकको यह बात नहीं जंची। खास करके रतलामके श्वेताम्बरी स्थानकवासी जैन सज्जनोंको।

"शिविरमें अेक पक्षका कहना था कि साथ खानेमें आपसका प्रेम बढ़ता है, जब कि दूसरे पक्षका कहना था कि अिस प्रकारका सहभोजन अस्वास्थ्यकर और शिविरमें अेक भद्दा नमूना पेश करनेवाला है।

"गांववालों पर अिसका बुरा असर पड़ रहा है।"

यदि यह सही है तो कहना चाहिये कि यह मानना गलत है — अेक वहम है कि अिस तरह खानेसे आपसका प्रेम बढ़ता है। सहभोजनका अर्थ यह नहीं है। छुआछूतके बिना सब लोग अेक पंगतमें बैठकर अपनी-अपनी थालीमें स्वच्छतापूर्वक अपना खाना खायें, यह ठीक है। अुसका अर्थ अेक ही पात्रमें खाना नहीं है।

२३–१२–'५५ **म० प्र०**

सर्वोदयके ध्येयके लिअे

श्री अेम० के० सेन लिखते हैं कि पूर्ण रूपसे सर्वोदयके ही ध्येयके लिअे काम करनेवाली अेक प्रेस अेजेन्सी कायम की गअी है, जिसका मकसद सर्वोदयके आदर्शोंके बारेमें समाचार, सूचना और लेख अिकट्ठे करके दैनिक पत्रों और सामयिक पत्रोंको बांटना होगा। अुसका दफ्तर सी–५२, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता–१२ में रहेगा।

अिसके साथ मैं अेक और खुशखबर जोड़ना चाहता हूं कि सर्व-सेवा-संघने अंग्रेजीमें 'भूदान' नामक अेक साअिक्लो स्टाअिलका अर्ध-साप्ताहिक बुलेटिन हैदराबादसे पिछले माह निकालना शुरू किया है। वह भी भूदानके जरिये सर्वोदयके ध्येयको आगे बढ़ानेके लिअे ही निकाला जाता है।

हम दोनोंकी पूर्ण सफलता चाहते हैं।

२०–१२–'५५ **म० प्र०**

(अंग्रेजीसे)

* १५ दिसम्बर, १९५५ के 'अे० आअी० सी० सी० अिकॉनामिक रिव्यू' से अुद्धृत।

www.vinoba.in

हरिजनसेवक

३१ दिसम्बर १९५५

नयी आर्थिक नीति

मैं पाठकोंका ध्यान अिस अंकमें अन्यत्र दिये गये श्री जवाहरलालजीके भाषणकी ओर खींचता हूं। वह अेक अप्रकाशित भाषणकी रिपोर्ट है, जो अुन्होंने ५ दिसम्बर, १९५५ को पार्लमेन्टमें कांग्रेस पार्टीकी बैठकमें दिया था। बेशक वह हमारी मौजूदा आर्थिक नीतिका बहुत महत्त्वपूर्ण बयान है। वह हमें अपनी आजकी आर्थिक विचारसरणी और विकासकी मंजिल पर प्रधानमंत्रीके रुख और दृष्टिको बताता है। यह मौका सचमुच बड़ा नाजुक और महत्त्वपूर्ण परिणाम लानेवाला है। अिसलिअे अुसके बारेमें आज हम जो निर्णय करेंगे, अुसका बड़ा दूरगामी महत्त्व होगा और हमारे देशके भविष्य पर अुसका बड़ा असर होगा।

आज हमारे देशकी आर्थिक प्रगतिके विषयमें अिन दो नारोंने मार्गदर्शक सिद्धान्तोंका रूप ले लिया है — पहला, अुद्योगीकरणके जरिये अुत्पादन बढ़ाना; दूसरा, छोटे पैमानेके ग्रामोद्योगोंका विस्तार करके लोगोंको अधिकाधिक कामधंधा देना। प्रधानमंत्री स्वभावतः अिस कठिन समस्याको हल करनेकी अपनी दृष्टिमें सावधान और जाग्रत रहना चाहते हैं। वे निश्चित रूपमें कहते हैं कि अिस विषयमें बुनियादी सिद्धान्तोंके बारेमें कोअी झगड़ा नहीं है। अुन्होंने कहा है: "सिद्धान्तोंके साथ मैं सहमत हूं, और अेक सिद्धान्त यह है कि हमें अम्बर चरखेको यथाशक्ति आगे बढ़ाना है।". दूसरा सिद्धान्त है अुत्पादनकी नअीसे नअी पद्धतियां अपनाकर 'बड़े पैमाने पर' अुत्पादनको निश्चित बनाना। अेक संयोजित आर्थिक प्रयत्नमें अिन दोनों सिद्धान्तोंका मेल हमें बैठाना होगा।

अिसलिअे समस्या यह है कि अिन दोनोंके बीच सन्तुलन कैसे कायम किया जाय? अुत्पादन बढ़ानेकी जरूरत तो साफ है। पश्चिमने अिसकी पद्धति बता दी है, और अुसमें लगभग रोज ही सुधार हो रहा है। लेकिन यहां हमारी भारतीय परिस्थितियोंमें अेक रुकावट आती है, अर्थात् 'यंत्रोद्योग-संबंधी बेकारी' की समस्या खड़ी होती है। जैसा कि प्रधानमंत्रीने कबूल किया है, "अगर कोअी चीज बेकारी पैदा करती है तो हमें सोचना होगा कि क्या किया जाय।" अिसलिअे हमें कामधंधा बढ़ानेकी व्यवस्था करनेके दूसरे और अगर ज्यादा नहीं तो अुतने ही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर ध्यान देना चाहिये।

भारतीय संविधानका आदेश है कि :

> "राज्य अुचित कानून बनाकर, या आर्थिक संगठन करके या दूसरे किसी मार्गसे अिस बातका प्रयत्न करेगा कि खेतिहरों, मिल-मजदूरों और दूसरे सारे कामगारोंको काम और पेटभर मजदूरी मिले, वे अैसी हालतोंमें काम करें जिनसे अिस बातका विश्वास हो कि अुनका रहन-सहन भले लोगों जैसा है, तथा वे फुरसतके समयका और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरोंका पूरा पूरा लाभ अुठा सकें। और खास करके —
>
> "राज्य गांवोंमें घरेलू अुद्योगोंको व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ानेका प्रयत्न करेगा।"

राज्यकी यह वैधानिक जिम्मेदारी है। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, "अिस प्रश्न पर पूंजीवादी दृष्टिकोणसे विचार करने पर भी यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हम लोगोंको कामधंधा न दे सकें तो हमें अुन्हें 'डोल' देना चाहिये। अिंग्लैण्ड और अुसके जैसे दूसरे देशोंको यही करना पड़ता है। . . . देशमें १ करोड़ लोगोंको 'डोल' देना हमें पुसा नहीं सकता। 'डोल' देना बुरी बात भी है। 'डोल' देनेके बजाय कामधंधा देना कहीं बेहतर है, भले वह काम आर्थिक दृष्टिसे नुकसान पहुंचानेवाला हो। . . . अैसी नीति पर अमल करना और भी बुरा है, जो अेकदम न सही परंतु धीरे धीरे भी यथाशक्ति बेकारी दूर करनेमें हमारी मदद नहीं करती।"

अेक ओर अुद्योगवाद और अुसके फलस्वरूप पैदा होनेवाली 'यंत्रोद्योग-संबंधी बेकारी' और दूसरी ओर कामधंधा बढ़ाने या अर्ध-बेकारी और पूर्ण बेकारीको दूर करनेकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताके अूपरसे दिखाअी देनेवाले अिस विरोधाभासके बीच मेल बैठाने और सन्तुलन कायम करनेकी समस्या आजके आर्थिक अितिहासकी अेक अनोखी समस्या है। अिसके लिअे अैसा ही अनोखा हल भी खोजा जाना चाहिये। अिसका मार्ग अम्बर चरखे जैसे औजारों द्वारा हमारी विशाल मानव-शक्तिका अुपयोग करनेकी विकेन्द्रित पद्धतिका विकास करनेसे मिल सकता है। यह हमारे गांवोंके लाखों घरोंमें विकेन्द्रीकरणकी कृषि-औद्योगिक अर्थरचनाको फैलानेका गांधीवादी मार्ग है। अिस अंकमें अुद्धृत किया गया प्रधानमंत्रीका भाषण अिस बातका काफी प्रमाण है कि अिस प्रश्नमें बड़े गंभीर मुद्दे समाये हुअे हैं। हमें बिना किसी पूर्वग्रहके या पश्चिमके आर्थिक या यंत्रोद्योगवादी दकियानुसीपनके पहलेसे बने-बनाये विचारोंके बिना धैर्यपूर्वक अिन मुद्दोंको हल करनेमें लगना चाहिये।

२१-१२-'५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

बम्बअी भारतकी दूसरी राजधानी

बम्बअी शहरको भारतकी दूसरी राजधानी बनानेका सुझाव (देखिये ता० १०-१२-'५५ के 'हरिजनसेवक' में 'दिल्ली और बम्बअी' नामक लेख) आगे बढ़कर दिल्ली तक पहुंचा है, यह देखकर आनन्द होता है। अखबारोंसे पता चलता है कि श्री विनोबाको यह सुझाव पसन्द है और अुन्होंने अिसे दिल्ली तक पहुंचाया है। देशकी प्रजाकी ओरसे अुन्होंने अिस अच्छी बातको या अुचित विचारको आगे बढ़ाया है, अिसके लिअे मैं अुन्हें धन्यवाद देता हूं।

बम्बअी शहरका अेक छोटासा अलग राज्य बनानेसे यह सुझाव जरूर अधिक अच्छा है। जो वर्तमान बम्बअी राज्यके तीन राज्य बनानेमें विश्वास रखते हैं, अुन्हें तो यह सुझाव अच्छा लगेगा ही। और मुझे अैसा भी लगता है कि अगर अिन दो सुझावोंमें से अेकका चुनाव करना हो तो महाराष्ट्रका मन भी बम्बअीको भारतकी दूसरी राजधानी बननेका गौरव प्रदान करनेवाले सुझावकी ओर ही झुकेगा। बम्बअी नगरीकी जनताको भी यह सुझाव पसन्द आयेगा, क्योंकि अुसकी जनतामें अिस प्रश्नको लेकर जो दुःखद स्थिति, मनमुटाव, जनूनी कड़वाहट और हिंसा पैदा हुअी है, वह भी अिस तरहकी योजनासे ही मिटाअी और भुलाअी जा सकती है। सारे भारतको भी यह विचार पसन्द आयेगा, क्योंकि बम्बअी वास्तवमें तो व्यवहारकी दृष्टिसे आज भी भारतकी अेक प्रकारकी राजधानी है ही। अुस पर मुहर लगाना ही बाकी है।

अेक विचार यह प्रगट किया जाता है कि बम्बअीके राजनीतिक क्षेत्रके लोगोंको यह विचार शायद पसन्द नहीं आयेगा। स्वतंत्र धारासभा और मंत्रिमंडल वगैराकी सत्ता भोगनेका स्वप्न अुनके दिमाग पर हावी हो गया हो, तो वह अिस सुझावसे खतम हो जाता है। बात ठीक है। परंतु वे लोग भी अिस दूसरे सुझावको अुड़ा तो नहीं देंगे। अितना तो वे भी कबूल करेंगे कि यह सुझाव ज्यादा अच्छा है। तब सवाल केवल व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका रह जाता है। मेरा विश्वास है कि अैसे व्यक्ति-

www.vinoba.in

गत विचार बम्बअीके प्रति अुनकी सच्ची भक्ति और प्रेमके सामने टिक नहीं सकेंगे। अुनकी नगरीको भारतकी दूसरी राजधानीका अपूर्व गौरव और सम्मान मिल रहा है, यह क्या कम संतोषकी बात है?

ता० १०-१२-'५५ के अुपरोक्त लेखमें मैंने राज्य-पुनर्रचना कमीशनकी रिपोर्टके दिल्ली-प्रकरणका अुल्लेख किया था। अुसके ५९३वें पैरेमें अैसी दलीलकी चर्चा करते हुअे कहा गया है कि दिल्लीको संघ-सरकारकी सीधी हुकूमतमें रखा जाय तो "दिल्लीके लोगोंको अेक राज्यकी प्रजाके नाते स्वराज्यका अुपभोग करनेका मौका नहीं मिलेगा; यह अेक प्रतिगामी कदम माना जायगा।" अिसके जवाबमें रिपोर्टमें कहा गया है कि "राष्ट्रकी राजधानीमें रहनेवाले लोगोंको अेक खास लाभदायक दर्जा प्राप्त होता है, अिसलिअे अुसके बदलेमें थोड़ा त्याग करनेके लिअे तो अुन्हें तैयार रहना ही चाहिये।" यह सामान्य प्रथा है कि दुनियामें किसी भी राष्ट्रकी राजधानी राष्ट्रके सीधे शासनमें ही रहती है। यह होते हुअे भी हमारे देशमें तो अैसा है कि राजधानीकी प्रजाका पार्लमेन्टमें प्रतिनिधित्व रहेगा। अिसलिअे वे संघ-सरकारमें अवश्य भाग ले सकेंगे। अिसके सिवा, राजधानीका नागरिक जीवन अुसकी प्रजाके रचे हुअे कार्पोरेशनके हाथमें होगा। अुसके अधिकार, कर्तव्य और अुसकी सत्ता सामान्यसे अधिक होगी। अिसके अलावा, बम्बअी नगरके पोर्ट ट्रस्ट तथा पुलिस वगैरा महकमों और कार्पोरेशनको अेक साथ गूंथकर अेक विशेष व्यवस्थाकी रचना की जा सकती है — की जानी चाहिये। अुसमें नगरकी प्रजा अपना नगर-स्वराज्य पूरी तरह भोग सकेगी। कहनेका मतलब यह कि राजधानी बननेसे बम्बअी नगरकी प्रजा स्वराज्यके अुपभोगका लाभ खोयेगी नहीं, बल्कि अपने प्रदेशके अनुरूप ढंगसे अच्छी तरह अुसका अुपभोग कर सकेगी।

रिपोर्टके ५९० वें पैरेमें राजधानीके लिअे जरूरी प्रदेश विस्तारकी चर्चा करते हुअे कहा गया है कि राज्यके लिअे अधिक विस्तार चाहिये। लेकिन राजधानीके लिअे अुतना नहीं चाहिये। राजधानीके लिअे तो अुसके भावी विकासके अन्दाजसे जितना भूभाग आवश्यक हो अुतना ही चाहिये। यह चीज बम्बअीको भारतकी दूसरी राजधानी बनाया जाय तो अुस पर भी लागू होती है।

पार्लमेन्टमें बम्बअीके विषयमें चर्चा हो चुकी है। अुसमें महाराष्ट्रके मुख्य सदस्योंने जो कुछ कहा, अुससे अिस बातके और ज्यादा कारण जाननेको मिलते हैं कि कमीशनकी द्विभाषी राज्यकी सिफारिश किस तरह अव्यावहारिक और टिक न सकने जैसी है। अिसलिअे अुसे रद्द मान कर ही चलना चाहिये — यह महाराष्ट्रका विचार महाराष्ट्रसे बाहर भी जड़ पकड़ता जा रहा है। अिसके कारण भले अुन अुन प्रदेशोंके लोगोंके अलग अलग हों, परंतु अितना तो स्पष्ट है कि बम्बअीके द्विभाषी राज्यकी बात बेकार है। तो फिर क्या किया जाय? पार्लमेन्टमें जिम्मेदार व्यक्तियोंने यह बताया है कि कांग्रेस कार्यकारिणीकी तीन राज्य बनानेकी सूचनाको बम्बअी राज्यके सारे पक्षोंने दूसरे नम्बर पर पसन्द किया है। अिसके आधार पर आगे बढ़कर अिस सूचनाको अधिक स्वागतयोग्य बनानेका विचार करना है। अिसमें बम्बअीको राष्ट्रकी दूसरी राजधानी बनानेका सुझाव अुपयोगी सिद्ध हो सकता है। सब मिलकर अिस पर विचार करें और गअी-गुजरी बातोंको भूलकर अिस विषयमें अेकमत हो जायं, तो अुसमें सभीकी शोभा बढ़ेगी और बम्बअी नगरी सुन्दर ढंगसे फिर अेक होकर अपने जीवनका विकास करेगी।

२६-१२-'५५ **मगनभाई देसाई**

(गुजरातीसे)

सफाअी-कामगारोंका सवाल

अेक समय अिस विषयमें चर्चा चल रही थी कि यंत्रोद्योगोंके बजाय ग्रामोद्योगों द्वारा बेकारी दूर हो — अधिक लोगोंको काम मिले तो ज्यादा अच्छा है। अिसे बिलकुल नापसन्द करनेवाले अेक यंत्रोद्योगवादके अभिमानीने ताना मारते हुअे कहा, "पाखाना-सफाअीके लिअे भी अैसा ही सोचें तो बहुत लोगोंको काम मिल सकता है!"

यह बात सुनकर किसी भी देशाभिमानी भारतीयको दुःख होनेके साथ गुस्सा आये बिना नहीं रहेगा। अिसमें छिपी क्रूर मूर्खताकी हद हो गअी है!

अिस परसे मुझे अेक अिसी तरहकी क्रूर मूर्खताकी दूसरी बात याद आअी, जो १९३७ में गांधीजीकी बुनियादी तालीमकी कल्पनाके निकलने पर अेक विद्वान सम्पादकने कही थी। अुन्होंने अपने अंग्रेजी अखबारमें लिखा था, "पड़ोसमें चलनेवाले अुद्योगके द्वारा शिक्षण देनेकी बात यदि बम्बअीके अुपनगर बांदरामें लागू करनी हो, तो वहां कसाअीखानेके अुद्योग द्वारा बच्चोंको शिक्षण देना चाहिये!"

परंतु अैसी बातोंका कड़वा घूंट पी जाना चाहिये। यह सच है कि वे कहनेवालेके मनमें गांधीजीकी सूचनाके खिलाफ रही सख्त नापसन्दगी बताती हैं। खैर।

पाखाना-सफाअीकी मुख्य बातका विचार करें। शहरोंमें गटरोंके जरिये यह काम होता है; लेकिन सभी बड़े शहरों और गांवोंमें गटरें नहीं होतीं। अैसे सब स्थानों पर तो म्युनिसिपैलिटी सफाअी-कामगारोंको रखकर यह काम अुनसे करवाती है। अिसमें यंत्रोद्योगका कोअी विचार भी नहीं करता। गटर बनवायें तो भी अुसे साफ तो रखना ही पड़ता है। अिस कामके लिअे भी लोगोंको नौकर रखना पड़ता है। अिसलिअे पाखाना-सफाअीसे अधिक रोजी मिलनेकी बात तो बेसमझी और अज्ञानकी ही मानी जायगी।

लेकिन अिसमें भी प्रश्न दूसरा ही है। अिन कामगारोंकी हालत और तनखाहें कैसी हैं? आज अिन प्रश्नोंकी जो अुपेक्षा की जाती है वह अक्षम्य है। बम्बअी राज्यमें अिन बातोंका विचार करनेके लिअे बर्वे-समिति कायम की गअी थी। अुसकी बहुत मर्यादित सिफारिशों पर अमल करनेमें भी कअी जगह आनाकानी की गअी। ये सिफारिशें कोअी अंतिम नहीं थीं। सच पूछा जाय तो अिस दिशामें अुनसे भी आगे जाना चाहिये।

पाखाना-सफाअी वगैराके बारेमें कुछ लोग अैसा कहते हैं कि हरिजनोंको यह काम ही छोड़ देना चाहिये। अिसके बिना सवर्ण हिन्दू समाजको भान नहीं आयेगा। हरिजन यह काम छोड़ें ही नहीं, अैसा कोअी अुनसे कह नहीं सकता। भारतके नागरिकोंके नाते अुन्हें कोअी भी काम करनेका अधिकार है। परंतु अैसा मानकर तो वह हरगिज नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि वह काम बुरा है या न करने जैसा है। सच्चा सुधार तो यह होना चाहिये कि समाजके लिअे पाखाना-सफाअीका काम नीचा है, अिस तरहकी भावना मिट जानी चाहिये। अिसीलिअे गांधीजी हमेशा कहा करते थे कि मैला अुठानेका काम तो हमारी मां करती है; अुसे नीचा या हलका कौन कह सकता है? यह काम हर-अेकको करना चाहिये। अिसीलिअे बुनियादी तालीममें अुसे स्थान दिया जाता है। प्रत्येक शाला अपना पाखाना और पेशाबघर रखे और बालक समझके साथ अुनकी सफाअी करना सीखें, तो वे अनुबन्धपूर्वक स्वास्थ्य-विज्ञान भी सीखेंगे और सफाअीके नियमोंका पालन करना भी अुन्हें अपने-आप आ जायगा। अिस तरहकी क्रान्ति शिक्षणमें हो, तो ही हमारी जनताके गलत संस्कार अेक पीढ़ीमें दूर हो सकते हैं। पाखाना-सफाअी और झाड़ू लगाकर

www.vinoba.in

कचरा-कूड़ा साफ करनेका काम अन्तमें तो हमेशा विकेन्द्रित ही रहनेवाला है। हर घरको और हर व्यक्तिको अुसका ध्यान रखना चाहिये। सारे समाजका जो कूड़ा-कचरा अिकट्ठा हो अुसकी अुचित व्यवस्था करके अुससे सोने जैसा कीमती खाद तैयार करनेके बारेमें म्युनिसिपैलिटियों तथा सरकारोंको योजनाबद्ध विचार करना चाहिये। अिस संबंधमें योजना-कमीशन कुछ नहीं करता, यह बड़े दुःखकी बात है। अैसी हालतमें यह काम राज्य-सरकारोंको अपने स्वास्थ्य-विभाग और स्थानीय स्वराज्य-विभागके मारफत करना चाहिये। अिसके लिअे अेक आवाजसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रयत्न किया जाय, तो अस्पृश्यता-निवारणके काम पर अुसका अच्छा असर होगा। और देशके लोकमानस तथा शिक्षणमें भी अुससे जरूर फर्क पड़ेगा।

२१-१२-'५५ **मगनभाई देसाई**

(गुजरातीसे)

देशी भाषायें और राजकाज

रेल्वे बोर्डने अपने विभागमें यह आज्ञा निकाली है कि स्टेशनों पर तरह तरहके जो तख्ते लगाये जाते हैं, अुनमें अमुक अंग्रेजी शब्दोंके लिअे अमुक हिन्दी पर्यायोंका अुपयोग किया जाय। अिसके पहले अुन अंग्रेजी शब्दोंके लिअे अमुक हिन्दी शब्द रचे गये थे और तख्तों पर वे शब्द लिखे जाने लगे थे। वे शब्द कैसे विचित्र थे, यह नीचेके कुछ अुदाहरणोंसे मालूम होगा। Exit = प्रस्थान। Waiting Room = प्रतीक्षालय। (for Ladies = स्त्री-प्रतीक्षालय!) आदि।

अब जो शब्द सुझाये गये हैं अुनमें बहुत सुधार हो गया है। यह बताता है कि पारिभाषिक शब्दोंकी रचना धीरे-धीरे केवल संस्कृतसे लदे हुअे अनुवादसे बाहर निकल रही है। यह बहुत स्वागतके योग्य परिवर्तन है, जो सरकारके सभी विभागोंमें फैलना चाहिये — खास करके शिक्षा-विभागके पारिभाषिक शब्दोंकी रचनासे संबंधित मंडलमें; आज तो वह अिस दिशामें क्या कर रहा है, अिसका लोगोंको कुछ पता ही नहीं चलता!

रेल्वे बोर्ड द्वारा सुझाये गये नये शब्दोंके नमूने अखबारोंके संवाददाताने दिये हैं, जो मैं नीचे देता हूं:

'प्लेटफार्म' और 'स्टेशन मास्टर' शब्द मूल रूपमें ही रहेंगे। (गुजरातीमें प्लेटफार्मके तद्भव रूपमें 'फलाट' कहा जाता है, जो अपनाने जैसा माना जा सकता है।)

Assistant = सहायक

Exit = बाहर

Entrance = अन्दर

Parcel Outward = जानेवाला पारसल

Parcel Inward = आनेवाला पारसल

अैसे सरल और लोगोंकी समझमें आने लायक शब्द सुझानेके लिअे रेल्वे बोर्डको धन्यवाद देना चाहिये। अिसी तरह अगर दूसरे सरकारी विभाग भी काम करने लगें, तो अंग्रेजीसे हिन्दी पर पहुंचनेमें पंडित लोग और सरकारी अधिकारी भय दिखाकर जो देर करवाते हैं वह तुरन्त बन्द हो जाय। असल बात अिस काममें लगनेकी यानी लोगोंमें प्रचलित शब्दोंको अपनाते जानेकी और अुनका अुपयोग शुरू करनेकी है। अेक बार अिस कामकी हवा फैली कि लोग भी अिसमें मदद करने लगेंगे और कामको तेजीसे आगे बढ़ानेमें सहयोग देंगे।

रेल्वे बोर्डको अब दूसरा काम यह करना है कि वह लोगोंके साथ अपना पत्रव्यवहार सादी हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओंमें शुरू कर दे। अिसमें कानून रुकावट नहीं डालेगा। अिस तरह यदि केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारोंके सारे विभाग लोगोंके साथ देशी भाषाओंमें पत्रव्यवहार शुरू कर दें तो भाषा-विषयक क्रान्ति तुरन्त शुरू हो जायगी। अिसके बिना १५ वर्षमें जो परिवर्तन करनेकी अपेक्षा संविधानमें रखी गअी है, अुसका वातावरण नहीं पैदा हो सकेगा। प्रान्तोंकी नवरचनाके बाद सरकारोंको यह महान कार्य हाथमें लेना चाहिये।

१२-११-'५५ **मगनभाई देसाई**

(गुजरातीसे)

वनस्पति अपना सिर अुठा रहा है

वनस्पति अुद्योगके पीछे जो खतरे छिपे हैं, अुनके बारेमें हम हमेशा सरकारको और लोगोंको चेतावनी देते रहे हैं। वह घीके व्यापारको नष्ट करता है, तेलघानीके अुद्योगको बरबाद करता है और घीमें मिलावट करने लायक चीज मुहैया करके धोखेसे लोगोंको पोषक खुराकसे वंचित रखता है। आखिर अितने समय बाद सरकार अुसकी बुराअियोंके प्रति जाग्रत होती दिखाअी देती है।

केन्द्रीय सरकारके अन्न और कृषि मंत्रालयके बाजार और निरीक्षणसे सम्बन्ध रखनेवाले संचालक-मंडलने 'घीका अध्ययन' नामक अेक पुस्तिका निकाली है। भारत-सरकारके संचालक-मंडलने भारतके ३४ शहरोंमें हाल ही घीके नमूनोंकी जो जांच की थी, वह बताती है कि बाजारमें बेचे जानेवाले घीमें व्यापक रूपमें मिलावट की जाती है। औसत ग्राहकके लिअे बाजारमें मिलनेवाले घीकी शकल, स्वाद या गंधसे अुसकी परख करना असंभव होता है। जो नमूने अिकट्ठे किये गये थे, अुनमें से ३३ प्रतिशतमें बिलकुल घी नहीं था। २५ प्रतिशत नमूनोंमें पचास प्रतिशत तक मिलावट थी और ३३ प्रतिशतमें घीके कुछ निशान ही पाये गये थे। कहा गया है कि सबसे ज्यादा मिलाअी जानेवाली चीज वनस्पति था। और काममें लिया जानेवाला अैसा घी भैंस और गायके मक्खनके मिश्रणसे बनाया जाता है। केवल आठ नमूने मिलावटसे मुक्त थे, लेकिन "पोषणकी दृष्टिसे बहुत घटिया थे, जिनमें तीन प्रतिशतसे भी अधिक खट्टी चरबीवाले तत्त्व थे।"

जुलाअीसे सितंबर १९५२ तक जो ८४ नमूने अिकट्ठे किये गये थे, अुनमें से ५६ में वनस्पतिकी चरबी मिलाअी गअी थी; दूसरे २० नमूनोंके गुणके बारेमें शंका थी और अुनके बकरी और भेड़का घी होनेकी शंका थी।

घीके नमूनोंका यह विश्लेषण मैसूरकी केन्द्रीय अन्न टेकनिकल अनुसंधानशाला द्वारा और कानपुर तथा राजकोटके संचालक-मंडलकी नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया था।

रिपोर्टमें कहा गया है कि देशके लगभग हर भागमें अधिकसे अधिक जो चीज घीमें मिलाअी जाती है, वह वनस्पति है।

वनस्पतिके अुत्पादक अेक संघ बनाकर संयुक्त रूपमें अपने मालका विज्ञापन करते हैं। हम अिस बातकी हिमायत करते रहे हैं कि अन्न और दूसरे खाद्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञापनों पर यह नियंत्रण लगाया जाना चाहिये कि स्वास्थ्य-मंत्रालयकी मंजूरीके बिना वे न निकाले जायं। अिन विज्ञापनोंको बिक्रीके पदार्थोंमें रहे तत्त्वोंका स्पष्ट वर्णन करना चाहिये।

भोलीभाली सामान्य जनताके हितमें अैसे कदम निहायत जरूरी हैं। पोषणकी दृष्टिसे हमारी जनताका भोजन बहुत घटिया होता है और अिस कमीको और बढ़ानेके लिअे सरकार गरीब जनताकी रक्षा करनेके बदले अुसके अज्ञानका नाजायज फायदा अुठानेके लिअे अुत्पादकोंको बढ़ावा देती है। हम आशा करते हैं कि कमसे कम अब तो सरकार ग्राहकोंकी रक्षाके लिअे गहरा विचार करके अिस दिशामें अुचित कदम जरूर अुठायेगी।*

(अंग्रेजीसे) **जे० सी० कुमारप्पा**

* दिसम्बर १९५५ की 'ग्रामोद्योग पत्रिका' से अुद्धृत।

www.vinoba.in

मिल बनाम अम्बर चरखा

अैसा कहा जा सकता है कि मैं कपड़ेकी खरीद, बिक्री और अुत्पादनके व्यवसायमें जन्मसे ही पड़ा हुआ हूं। और आजके कपड़ा तैयार करनेवाले तथा कपड़ेका अुपयोग करनेवाले सारे देशोंका दौरा भी मैंने किया है। लगभग पच्चीस-छब्बीस वर्षके अपने अनुभवसे मैं कहूंगा कि अंबर चरखा ही हमारी ग्रामजनताकी बेकारी दूर करनेका बड़ेसे बड़ा साधन है।

वर्षोंसे कपड़ा अुत्पन्न करनेवाले अेक कारखानेदारके नाते भी मैं दावेके साथ कहूंगा कि अम्बर चरखेका अर्थ है कपड़ेके मिल-अुद्योगका विकेन्द्रीकरण।

कपड़ा-मिलोंके मालिकोंकी चिन्ताको हम समझ सकते हैं। मैं अुनमें से ही अेक हूं। अम्बर चरखेके अुपयोगसे यंत्रोंके बल पर चलनेवाली बड़ी मिलों पर जरूर असर होगा। परन्तु यह असर देशके लाखों बेकार लोगोंको काम देनेकी तुलनामें कुछ नहीं है।

बड़ी मिलोंके कपड़ेकी कीमतकी तुलना अम्बर चरखेके सूत तथा कपड़ेकी कीमतके साथ करनेवाले लोग यह बात आसानीसे भूल जाते हैं कि भारतके मिल-अुद्योगको बाहरके कपड़ेके खिलाफ सौ प्रतिशत आयात-महसूलका रक्षण प्राप्त है। अितना ही नहीं, विदेशोंसे कपड़ा मंगानेकी भी लगभग पूरी मनाही है।

मेरा यह विश्वास है कि अम्बर चरखेको अितना रक्षण तो क्या, कपड़ा मिल-अुद्योगको मिलनेवाले रक्षणका अमुक प्रतिशत रक्षण या मदद भी मिले, तो यह सिद्ध हो जायगा कि कपड़ा-अुद्योगका विकेन्द्रीकरण अिस देशके लिअे रामबाण अिलाज है।

कपड़ा मिल-अुद्योगको सरकारकी ओरसे जो बिजली, पानी, जमीन, पूंजी तथा अन्य सुविधायें और रक्षण प्राप्त होते हैं, अुतनी सब सुविधायें और मदद या अुनका अमुक प्रतिशत भी अगर अम्बर चरखे जैसे भारतके लाखों गरीबोंको रोजी देनेवाले साधनों और औजारोंको मिले तो हमारा देश जल्दी अुन्नत और खुशहाल बनेगा।

यह निश्चित है कि जब हमारे लाखों गांवोंमें बिजली, अच्छी सड़कें तथा डाक-तार और यातायातकी सुविधायें पहुंच जायंगी, तब शहरोंमें कृत्रिम ढंगसे चलनेवाले बड़े अुद्योगोंका अन्त आ जायगा। अिसीलिअे स्थापित स्वार्थवाले लोग गांवोंमें बिजली, पानी, डाक-तार, यातायात वगैराकी सुविधायें दाखिल करनेमें ढिलाअी करते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारीने भारतके अुद्योग-मंत्रीके नाते छोटे और बड़े तथा शहरों और गांवोंके अुद्योगोंकी ओर समान दृष्टि रखनेके बदले कपड़ेके केन्द्रित मिल-अुद्योगका जो पक्ष लिया है, वह अन्यायपूर्ण और अशोभनीय है।

खादी और मिल-कपड़ेकी कीमतोंकी तुलना करनेवालोंको अेक बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि मिल-कपड़ेके अुत्पादनमें मिलनेवाली बिजली, पानी, रूअी, पैसे वगैराकी सुविधायें अगर खादी-अुत्पादन करनेमें मिलें, तो कपड़ेका केन्द्रित मिल-अुद्योग कभी भी विकेन्द्रित ग्रामोद्योगके सामने टिक नहीं सकता। अम्बर चरखा कपड़ेके मिल-अुद्योगके लिअे अेक जबरदस्त चुनौती है। अिसलिअे अुसका जन्म होते ही अुसे दबा देनेकी बातें हो रही हैं, जो देश तथा अुसके लाखों ग्रामजनोंके हितमें नहीं हैं।

(गुजरातीसे) **मणिलाल दोशी**

हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण

लेखक : **गांधीजी**

संपादक : **भारतन् कुमारप्पा**

कीमत १–८–० डाकखर्च ०–५–०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–१४

श्रद्धा और विचार

"अिस समय हर जगह धार्मिक पागलपन बढ़ता मालूम हो रहा है। छोटे-छोटे गांवोंमें साधु-संत धर्मके बहाने अपने पैर फैला रहे हैं। भोलीभाली प्रजाको धर्मके पीछे पागल बनाकर यज्ञ-याग कराते हैं और हजारों रुपयोंकी बरबादी करा रहे हैं। ये पैसे अगर प्रजाकी ओरसे दी गअी रकमके रूपमें पंचवर्षीय योजनाके लिअे खर्च किये जायं तो ग्राम-विकासके बहुतसे काम हो सकते हैं। क्या अैसे धार्मिक पागलपनको आप रोक नहीं सकते?"

अेक पाठकने अैसा प्रश्न किया है। अैसा प्रश्न अुठ सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सरकारें बड़ी बड़ी दावतें और समारोह करती हैं (मिसालके लिअे, अभी अभी जो विदेशी मेहमान आये थे अुनके लिअे)। यह पैसा बचाकर अगर पंचवर्षीय योजनामें लगाया जाय तो देशको कितना लाभ हो? अिसी तरह थोड़े समय पहले अर्थमंत्री श्री देशमुखने कहा था कि लोग शादियों और जाति-भोजोंमें जो पैसा खर्च करते हैं, वह बचाया जाय तो योजनाके लिअे कितना अुपयोगी हो सकता है!

यहां असल बात हमारी श्रद्धाकी और अुस परसे आंकी जानेवाली किसी चीजकी कीमत और महत्त्वकी है। अुदाहरणके लिअे, पत्रलेखकको लगता है कि लोग धर्म मानकर यज्ञ-यागके पीछे जो पैसा खर्च करते हैं वह निरा पागलपन है; अैसी समझवाले लोग भोले हैं अिसीलिअे 'साधु-संत' अुन्हें भुलावेमें डालते हैं। अर्थात् लोगोंमें पुराने धार्मिक रीत-रिवाजोंके बारेमें जो परम्परागत श्रद्धा है, वह अिन भाअीको अच्छी नहीं लगती। अुन्हें पंचवर्षीय योजनामें अधिक श्रद्धा है।

अिस योजनाको भी नये प्रकारका 'यज्ञ' क्यों नहीं कहा जा सकता? अुसी प्रकार जिस प्रकार जवाहरलालजी भाखरा-नंगल वगैरा बांधोंको नये 'तीर्थ' मानते हैं।

और अिन नये यज्ञों और तीर्थोंके विषयमें भी अुनके दाव-पेच या शास्त्र जाननेवाले — अुपरोक्त 'साधु-सन्तों जैसे — निष्णात लोग नहीं होते? और अुनमें भी क्या धूर्त, ठग या रिश्वतखोर नहीं होते?

अिस प्रकार यहां मैं विचारकी तुलना जो कर रहा हूं वह कड़ी मालूम हो सकती है। लेकिन अैसा मैं केवल विचारकी स्पष्टता और अुदारताकी जरूरत बतानेके लिअे ही कहता हूं। अिससे ज्यादा गहरे अर्थमें अिस तुलनाको न खींचनेकी मैं पाठकोंसे प्रार्थना करता हूं। जहां मूल श्रद्धाका सवाल हो, वहां अैसे श्रद्धा-भेदको भी ध्यानमें रखकर विचार किया जाय तो अुसमें अधिक नम्रता और स्पष्टता आनेकी संभावना रहती है। अिसीलिअे मैंने अूपरकी चर्चा की है।

समाजकी अन्य बातोंकी तरह धर्मके विषयमें भी रूढ़िके रूपमें यज्ञ-याग, पूजा-पाठ वगैरा चलता है। अुसमें संशोधन करना तथा विचार और विवेकको जाग्रत रखना जरूरी है। परन्तु यह काम वे ही कर सकते हैं, जिनका धर्मके प्रति आदर और श्रद्धा हो। आजकल जिन लोगोंमें यह आदर और श्रद्धा कम होती है, वे धर्मकी हंसी अुड़ायें तो यह अुचित नहीं माना जायगा। धर्म अन्तमें तो स्वयं पालने और अुसी तरह प्रचार करनेकी वस्तु है। और अुसके बाहरी रूप अगर समाजकी नीति-रीति और मर्यादासे बाहर न हों अथवा समाज-हितकी दृष्टिसे निन्दाके पात्र न हों, तो अुनके विषयमें समाजके लोगोंमें परस्पर सहिष्णुता और समभावनाके गुणोंका विकास होना चाहिये। वर्ना हमारे जैसे अनेक धर्मोंवाले देशमें सारी प्रजा अेक साथ नहीं रह सकती। अिसलिअे हमें सर्वधर्म-सहभावका भी खयाल रखना चाहिये।

१५-१२-'५५ **मगनभाई देसाई**

(गुजरातीसे)

www.vinoba.in

कल्याण-राज्यसे लोकराज्यकी ओर

स्वराज्यके बाद वेलफेअर स्टेट (कल्याण-राज्य) का देशमें आरम्भ किया गया। कल्याण-राज्यका अर्थ है अधिकसे अधिक सत्ता कुछ व्यक्तियोंके हाथोंमें रहेगी और लोगोंका सारा जीवन वे व्यक्ति नियंत्रित करेंगे। कुल देशके पांच लाख देहातोंकी योजना दिल्लीमें बनेगी। जीवनके जितने अंग-प्रत्यंग हैं, अुनके विषयमें दिल्लीमें ही बातें तय होंगी। समाजमें क्या-क्या सुधार हों, शादियां किस ढंगसे हों, छूत-अछूतका भेद कैसे निवारण किया जाय, देशमें कौनसी चिकित्सा-पद्धति लागू की जाय, हिन्दुस्तानमें किस भाषाका प्रचलन चाहिये, सिनेमा किस ढंगसे चलने चाहिये अित्यादि जीवनके विषयोंमें दिल्लीमें योजना तय होगी। यदि अितनी अधिक सत्ता हम केन्द्रको देते हैं, तो सारा जन-समुदाय पराधीन हो जाता है, अनाथ बनता है। अिस वास्ते दिल्लीकी सत्ता ही कम होनी चाहिये। परमेश्वरने हरअेकको जितनी जरूरत है, अुतनी बुद्धि बांट दी है और खुद क्षीरसागरमें शयन करता है। अगर अुसने कुल अक्लका भंडार अपने पास रखा होता, तो वह पसीना-पसीना हो जाता। परन्तु अुसने मनुष्योंको और प्राणियोंको बुद्धि दे दी है और अितना तटस्थ रहता है वह कि कुछ लोग कहते हैं कि वह है ही नहीं।

सर्वोत्तम सत्ताका यह लक्षण है कि अुसका विभाजन सार्वत्रिक होता है। सर्वोत्तम सत्ता वह होती है जिसके बारेमें यह शंका होती है कि कोअी सत्ता चलाता भी है या नहीं? हमें यह शंका होनी चाहिये कि दिल्लीमें कोअी राज्य चलाता है या नहीं? कोअी कहेंगे, 'हां, दिल्लीमें राज्य चलता है, बीच-बीचमें वहां सज्जन आते हैं, सभा होती है, चर्चा करते हैं।' कोअी कहेंगे, 'वहां कोअी राज्य चलाता है अैसा नहीं दीखता है, क्योंकि हमारे गांवका कारोबार तो हम ही देखते हैं।' केन्द्रीय सत्ता अिस तरहसे परमेश्वरी सत्ताका अनुकरण करनेवाली होनी चाहिये।

सत्ताका विभाजन होना चाहिये और ज्यादासे ज्यादा अधिकार गांवमें होना चाहिये। अेक गांव हो या दो-चार-पांच छोटे गांव मिलकर अेक क्षेत्र बने हों, लेकिन छोटी-छोटी अिकाअियोंमें पूर्ण सत्ता होनी चाहिये। गांव-गांवमें ग्राम-योजना चलेगी। ग्राम-योजना ग्राममें होनी चाहिये। आज तो सारे राष्ट्रके लिअे दिल्लीमें योजना बनती है। अिस तरीकेसे अपना देश बन नहीं सकता, अिसकी ताकत नहीं बढ़ सकती। अिसलिअे होना यह चाहिये कि गांवका कारोबार पूरा-पूरा गांवमें ही हो। गांवके लिअे आयात-निर्यात रोकनेका अधिकार गांवको होना चाहिये। गांववाले अपने लिअे जो फैसला करेंगे वह सर्वानुमतिसे होगा।

अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अहिंसा पर खड़ा हो, तो हमें दूसरे ढंगसे सोचना चाहिये। अुसके लिअे हमें अपने समाजकी रचना अपने विचारसे करनी चाहिये। केवल पश्चिमका अनुकरण नहीं चलेगा। कुल दुनियाके देशोंके लोग शांतिके लिअे प्यासे हैं, क्योंकि वे अेटम और हाअिड्रोजनकी शक्तिके मारे भयभीत हैं। वे समझ गये हैं कि अिससे दुनियाका नाश होगा, कुछ काम नहीं होगा। अगर हम शांति चाहते हैं, तो शांतिके अनुकूल रचना करनी होगी। करना यह होगा कि सरकारका अेक-अेक कार्य जनताको अपने हाथमें लेना होगा। सरकारका काम कम होते होते सरकार क्षीण हो जाय, अैसी योजना करनी होगी। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी मैं प्रेम-समाजमें बोल रहा था। प्रेम-समाजके लोग बीमारोंकी और दुखियोंकी सेवा करते हैं। हिन्दुस्तानके तमाम बीमारोंकी सेवा करनेका काम जनता अुठा लेगी तो सरकारका स्वास्थ्य-विभाग खतम हो जायगा। और यह होगा तो बहुत बड़ी बात बनेगी। जैसे रामकृष्ण मिशनके मठोंने सब दूर बीमारोंकी सेवाका काम अुठा लिया है, वैसी जगह-जगह संस्थाअें बनें और लोगोंकी तरफसे काम अुठा लिया जाय। फिर जनताकी जिस चिकित्सा पर श्रद्धा है वही पद्धति चलेगी। लोग अपनी शक्तिसे सारे काम चलायेंगे। सरकार जब तक है, तब तक अुस काममें थोड़ी मदद दे। परन्तु सरकारका चिकित्सा-विभाग नहीं रहेगा। फिर जो बी० सी० जी० वाला वाद चला है, वह अुठेगा नहीं। आज हालत यह है कि सरकार चाहेगी तो सब लड़कोंको बी० सी० जी० का अिंजेक्शन लगवायेगी। राजाजी अिस बारेमें बहुत बोल चुके हैं। यह सारा अिसलिअे होता है कि अिस देशने केन्द्रके हाथमें सब सत्ता सौंप दी है। हमारे बच्चोंको कैसी दवा देनी चाहिये, यह बात हम लोग तय करेंगे। आजकी हालत यह है कि आरोग्यके लिअे कौनसी पद्धति चले, यह सरकार सोचती है। हम कहते हैं कि यह बहुत बड़ा जुल्म है।

दूसरी मिसाल देता हूं। शिक्षण पर आज राज्यसत्ताका नियंत्रण है। जो पाठ्यपुस्तक अुत्तरप्रदेशकी सरकार तय करेगी, वही पाठ्यपुस्तक अुस प्रान्तके सब बच्चोंको पढ़नी होगी। अिसका मतलब यह है कि बच्चोंके दिमागोंमें अपने विचार ठूंसनेकी शक्ति सरकारके हाथोंमें आवे। अगर सरकार कम्युनिस्ट हो तो बच्चोंको कम्युनिज्म सिखायेगी। सरकार फासिस्ट हो तो सब बच्चोंको फासिज्म सिखायेगी। सरकार सोशलिस्ट हो तो बच्चोंको सोशलिज्म सिखाना होगा। पूंजीवादी हो तो पूंजीवादका गौरव सर्वत्र सिखाया जायगा। सरकार योजनावादी हो, तो योजनाकी महीमा बच्चोंके दिमागमें ठूंसी जायगी। मतलब यह है कि बच्चोंके दिमागको आजादी नहीं रहेगी। अिसलिअे हमारे देशमें माना गया था कि शिक्षण पर राज्यकी सत्ता होनी ही नहीं चाहिये। सान्दीपनि गुरु पर वसुदेवकी सत्ता नहीं चल सकती थी। वसुदेवका लड़का श्रीकृष्ण सेवक बन कर सांदीपनिके पास जा सकता था और सांदीपनि सुदामाके साथ लकड़ी चीरनेका काम कृष्णको देते थे। अब वहां पर कौनसी पाठ्यपुस्तक चलनी चाहिये, वह वसुदेव नहीं देखता था। क्षत्रियसत्ता — राज्यसत्ता शिक्षण पर हरगिज नहीं चल सकती। अिसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत भाषामें आज जितना विचार-स्वातंत्र्य है, अुतना कहीं नहीं दीख पड़ता। हिन्दू-धर्मके अन्दर छह छह दर्शन निकले और वे भी परस्पर विरोध करनेवाले — मीमांसाका खण्डन वेदांत करता है, वेदांतका खंडन मीमांसा करती है; सांख्यका खंडन वेदांत करता है, वेदांतका खंडन सांख्य करता है। लेकिन सांख्य भी हिन्दू है, वेदांत भी हिन्दू है और मीमांसा भी हिन्दू है। विचारका अितना स्वातंत्र्य यहां चल सका, अुसका कारण यही है कि राज्यसत्ताका कोअी काबू शिक्षण पर नहीं था। अिस तरहसे सरकारका अेक अेक कार्य जनताके हाथमें आयेगा और सरकारकी सत्ता क्षीण होती जायगी, तो दुनियामें अहिंसा भी टिकेगी और शांति भी टिकेगी। अगर केन्द्रीय सत्ताके हाथमें लोग रहेंगे, तो समझना चाहिये कि दुनिया खतरेमें है।

(१८ नवंबर, १९५५ के 'भूदान-यज्ञ' से) **विनोबा**

विषय-सूची

		पृष्ठ
हमारी बुनियादी आर्थिक दृष्टि	जवाहरलाल नेहरू	३४५
नयी आर्थिक नीति	मगनभाई देसाई	३४८
बम्बअी भारतकी दूसरी राजधानी	मगनभाई देसाई	३४८
सफाअी-कामगारोंका सवाल	मगनभाई देसाई	३४९
देशी भाषायें और राजकाज	मगनभाई देसाई	३५०
वनस्पति अपना सिर अुठा रहा है	जे० सी० कुमारप्पा	३५०
मिल बनाम अम्बर चरखा	मणिलाल दोशी	३५१
श्रद्धा और विचार	मगनभाई देसाई	३५१
कल्याण-राज्यसे लोकराज्यकी ओर	विनोबा	३५२
टिप्पणियां :		
संकुचित वृत्तिसे सावधान रहें	म० प्र०	३४७
गलत समझ	म० प्र०	३४७
सर्वोदयके ध्येयके लिअे	म० प्र०	३४७

www.vinoba.in